डूबते जहाज हैं ट्रम्प और मोदी.....

पेज एक का शेष

कावानाग को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के लिए नामांकित करना आजकल वहा का सबसे चर्चित मुद्दा बना हुआ है। कावानाग ने अपनी बेदाग छवि को लेकर टीवी साक्षात्कार में डींगें क्या मारीं कि उनके साथ की पढ़ी एक श्वेत प्रोफेसर क्रिस्टीन ब्लेसी फोर्ड ने सामने आकर उन पर स्कूल जीवन में यौन हमले का आरोप लगा दिया। साथ ही उनके बेतरह शराब पीने के भी किस्से सामने आये। सेनेट, जो ऐसे नामांकन पर बहुमत से मुहर लगती है, इस कदर बंट गयी कि मामला सीमित जांच के लिए एफबीआई के हवाले करना पड़ा। अमेरिका भर में महिलाओं ने इसे जेंडर न्याय का मुद्दा बना लिया है और मीडिया में कयास है कि ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी को नवम्बर में होने वाले मध्यावधि चुनाव में महिला वोटरों के गुस्से का खामियाजा भुगतना होगा।

इसी तरह भारत में आठ हजार करोड़ के बैंक कर्ज के डिफाल्टर देनदार विजय माल्या को वित्त मंत्री अरुण जेटली की शह से धन सम्पदा सहित लंदन भागने का मुद्दा बेहद चर्चित रहा है। सीबीआई, जो सीधे प्रधानमन्त्री के अधीन काम करती है, ने माल्या के लुक आउट नोटिस को 'पकड़ कर सूचित करो' से केवल 'सूचित करो' में बदल दिया था। स्वयं माल्या ने बताया और जेटली ने माना कि भागने से दो दिन पूर्व दोनों इसी सम्बन्ध में संसद में मिले भी थे।

कावानाग और जेटली जैसी बोझ छवि वाले पिछलग्गुओं को लगातार समर्थन देते रहना स्वयं ट्रम्प और मोदी के राजनीतिक चरित्र की भी बानगी है। लाख आलोचना के बावजूद ट्रम्प ने अपना टैक्स रिटर्न सार्वजनिक नहीं किया है। जानकारों का मानना है कि वे अपने वित्तीय घपलों को छिपा रहे हैं। इसी तरह मोदी की शैक्षणिक डिग्रियां भी अरसे से आरोपों के घेरे में चली आ रही हैं।

दूसरी तरफ, ट्रम्प और मोदी का बढ़बोला होना उनके योग्य सहयोगियों को बहुत देर तक रास नहीं आ पाना भी स्वाभाविक था। मोदी सरकार के तमाम आर्थिक सलाहकार एक-एक कर यूं ही नहीं अपनी जिम्मेदारियों से अलग होते गये हैं। कालाधन, नोटबंदी, रोजगार और रुपये की गिरती कीमत को लेकर प्रधानमन्त्री के रोजाना के झूठ वे आंकड़ों की बाजीगरी से कहाँ तक निभाते!

इसी तरह ट्रम्प का नजला भी निरंतर उनके प्रेस और कम्युनिकेशन अधिकारियों पर गिरता रहा है जो ट्रम्प के झूठ बोलने की गति से तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। अब तक व्हाइट हाउस के दो प्रेस सेक्रेटरी और दो कम्युनिकेशन डायरेक्टर इसीलिए पदों से हटाये जा चुके हैं।

स्वयं अपने लगाये अटॉर्नी जनरल जश सेशेल्स को ट्रम्प महीनों से सरेआम निकम्मा कह रहे हैं क्योंकि उनके कहे मुताबिक सेशल्स स्पेशल काउंसल रोबर्ट मुलर की उस विशेष जांच में दखल देने से परहेज कर रहे हैं जिसमें ट्रम्प की मदद के लिए राष्ट्रपति चुनाव में रूसी दखल के आरोपों की छान-बीन हो रही है। अमेरिका में अटॉर्नी जनरल ही न्याय विभाग का प्रमुख होता है। नवम्बर चुनाव में विपरीत असर को देखते हुए फिलहाल सेशेल्स की बर्खास्तगी रुकी हुयी है।

अमेरिका में 'फैक्ट चेकर' विश्लेषण के मुताबिक ट्रम्प अपने कार्यकाल के 601वें दिन पांच हजार झूठ या भ्रामक तथ्य बोलने तक पहुँच गये हैं। मोदी को लेकर ऐसा कोई विश्लेषण भारत में सामने न भी आया हो लेकिन उनका शायद ही कोई भाषण होगा जिसमें झूठ और गलतियों की भरमार न मिले। प्रधानमन्त्री का 'फेंकू' कहा जाना उनकी सारी सरकार के लिए शर्मनाक बात है। आश्चर्य नहीं कि दोनों की कैबिनेट में स्तरहीन व्यक्तियों की भरमार है।

मोदी, अपनी असफलताओं को कांग्रेस और नेहरू के मत्थे मढ़ने से आगे नहीं बढ़ सके और ट्रम्प अपने हर कदम को अमेरिकी इतिहास में सर्वश्रेष्ठ कहने से नहीं चूकते। पिछले महीने यूएन में भाषण देते हुये जब ट्रम्प ने यही दावा वहां भी दोहराया तो उपस्थित प्रतिनिधियों को बरबस हंसी आ गयी।

अमेरिका में गंभीरता से माना जा रहा है कि ट्रम्प, महाभियोग के रास्ते पद से हटाये जाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। भारत में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जो मानते हैं कि मोदी के नाम पर आगामी तीन विधान सभाओं के चुनाव में पुनः जीत हासिल कर पाना मुश्किल होगा।

कहते हैं जहाज डूबने से पहले चूहे भी निकल जाते हैं। जिस हिसाब से ट्रम्प और मोदी के कृपापात्र और सलाहकार चुपचाप निकल रहे हैं, कहीं उन्हें डूबता जहाज ही तो नहीं दिख रहा!

घरौंडा में भाजपा को झटका,

घरौंडा(प्रवीण कौशिक)-घरौंडा की पूर्व विधायिका व वरिष्ठ नेता रेखा राणा ने आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल को ज्वाइन कर लिया है। इसकी पुष्टि रेखा राणा के पुत्र द्वारा फोन पर की गई रेखा राणा ने भाजपा से इस्तीफा क्यों दिया, इसको लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में रेखा राणा से बात करनी चाही तो उनसे संपर्क नहीं हो सका । मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिए जाने के कारण भाजपा के लिए यह नुकसानदायक भी साबित हो सकता है ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं ।चर्चा रही कि भाजपा में रेखा राणा को कोई अहमियत नहीं दी जा रही थी और पार्टी के द्वारा उनकी अनदेखी की जा रही थी । शायद इसी वजह से वे पार्टी में घुटन महसूस कर रही थी जिसके कारण आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया और इनेलो से ही विधायक रही पार्टी में वापसी कर ली।

FASHION.IN

Available all types of ladies cotton kurties, Fancy Kurties, Jegin, legin, Fancy Top, T-Shirts, Trousers and imported material in wholesale price.

SPECIALITY IN FANCY TOP & FANCY KURTIES

लेडीज कपड़ों पर भारी छूट

एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।

Address : 5M/22, N.I.T. FARIDABAD NEAR DAYANAND WOMEN COLLEGE, ST. JOSEPH CONVENT SCHOOL ROAD . 9911489490

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5
2. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
4. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे
5. राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने
6. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास
7. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207

गतांक की चीर-फ़ाड़

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

सिपाहियों को मालूम है कि सत्ता में अपराधियों की भरमार है

मज़दूर मोर्चा के 7-13 अक्तूबर 2018 के अंक में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व स्थानीय ज्वलंत मुद्दों पर अनेक समाचार प्रकाशित हुए हैं। भारत की वर्तमान पुलिस व्यवस्था व प्रशासन औपनिवेशिक देन है। ब्रिटिश प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये एक नियमित पुलिस दल की स्थापना की थी। जब राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ तब पुलिस का इस्तेमाल उसे दबाने के लिये किया गया। पुलिस ने आम लोगों के साथ असहानुभूति पूर्ण रूख अपनाया। संसदीय समिति की 1813 की रिपोर्ट में बतलाया गया कि ''पुलिस ने शांतिप्रिय निवासियों को उसी तरह लूटा-मारा जैसे डकैत करते थे जिनको दबाने के लिये उसका गठन किया गया था।'' गवर्नर जनरल विलियम बैंटिक ने 1832 में लिखा ''जहां तक पुलिस का सवाल है वह जनता की रक्षक होने से कोसों दूर है।'' स्वतंत्रता के बाद भी पुलिस का औपनिवेशिक काल का रवैया बना रहा। अब अंग्रेजों की जगह भारतीय शासक आ गए जिन्होंने ब्रिटिश शासकों की तरह पुलिस का इस्तेमाल किया। सत्ता के जातिवाद प्रोफाइल का पुलिस के औपनिवेशिक व सामंती चरित्र से घालमेल सभी सरकारों में कमोबेश दिखता रहा है।

उत्तर प्रदेश में सत्ता सम्भालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था में सुधार के नाम पर एनकाउंटर वह भी पिछड़ों का खुला खेल खेला जाने लगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का मुसलमानों, यादवों और चमारों का योगी के 'ऑपरेशन क्लीन' और 'ठोक दो' का चेहरा बनता गया, जिसकी 'पुलिस की योगी छाप गुंडई का नमूना है विवेक तिवारी हत्याकांड' में बेबाक चर्चा की गई है। योगी सरकार के एनकाउंटर सैलाब के सामने राजनीतिक विरोधी, मीडिया, नागरिक संगठन, मानवाधिकार आयोग व न्यायपालिका भी विवश नज़र आ रहे थे। लखनऊ में बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐपल के मैनेजर विवेक तिवारी की 28 सितम्बर की हत्या ने सबको झकझोर कर रख दिया। 'मुस्कराना छोड़ ठहाका लगाइए कि आप खूनी लखनऊ में है: पुण्य प्रसून वाजपेयी' में पुलिस कांस्टेबल प्रशांत चौधरी द्वारा विवेक तिवारी की हत्या और सत्ता के अपराधीकरण का पर्दाफ़ाश किया गया है।

योगी के डेढ़ साल के कार्यकाल में यूपी पुलिस अपराध की रोकथाम के नाम पर आजमगढ से अलीगढ़ तक एनकाउंटर में अनेक लोगों की हत्या कर चुकी है, परंतु उनमें से एक भी मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की गई। लगभग 12 मामले अदालत में है पर चश्मदीद गवाह के अभाव में लटक रहे हैं और अदालत ने पुलिस को हत्यारा कहने में कोई झिझक नहीं दिखाई। विवेक तिवारी प्रकरण में यूपी के डीजीपी ने पुलिस विभाग की तरफ से माफ़ी मांगने में कोई देरी नहीं की जबकि मुख्यमंत्री योगी ने तिवारी की हत्या को पुलिस एनकाउंटर मानने से इन्कार कर दिया। तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी जो पहले इस पूरे कांड की सीबीआई जांच की मांग कर रही थी उसे योगी सरकार ने 40 लाख रुपये का मुआवज़ा, नौकरी और सरकारी आवास मुहैया कराने का आश्वासन देकर चुप करा दिया। हत्या के दोनों आरोपी सिपाही प्रशांत चौधरी व संदीप कुमार राणा की गिरफ़्तारी और नौकरी से निकाले जाने के विरुद्ध यूपी पुलिस में बगावत की स्थिति बन गई है। उनके चार समर्थक सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया जबकि 11 अन्य सिपाहियों को लाईन हाजिर कर दिया गया है।

इस कार्यवाही के विरोध में तथा आरोपी सिपाही प्रशान्त के समर्थन में पुलिस विभाग के उसके साथी लामबंद होने लगे हैं तथा अपनी ड्यूटी के बहिष्कार के आंदोलन को चलाने की भी योजना बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर उसके परिवार की अर्थीक सहायता के लिये अभियान चला दिया गया है जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप प्रशांत की पत्नी के मेरठ के स्टेट बैंक के खाते में लाखों रुपये जमा हो चुके हैं। गौरतलब है कि आरोपी की पत्नी भी सिपाही है।

सिपाहियों को मालूम है कि सत्ता में अपराधियों की भरमार है और पूरी राजनीति अपराधियों से पटी पड़ी है। मुख्यमंत्री योगी ने स्वयं अपने ऊपर से तीन आपराधिक मुकदमे कैबिनेट के ज़रिए समाप्त करा लिये थे तो फ़िर आरोपी कांस्टेबल को भी सत्ता बचायेगी ही।

हरियाणा में भी सत्ता के संरक्षण में सीपी साहब के निर्देश पर फ़रीदाबाद में पुलिस अधिकारियों ने फ़ाइनेंसरों का हिसाब-किताब चुकता कराने के लिये माफ़िया की तरह एक बिल्डर का अपहरण करके बुरी तरह पीटा और संबंधित काग़जों पर बिल्डर के हस्ताक्षर करा लिये, जिसका '' 'ईमानदार' खट्टर की पुलिस द्वारा दहशत से वसूली का एक नमूना '' में उजाग़र किया गया है। यह स्वतंत्र भारत के शासन, प्रशासन व पुलिस व्यवस्था पर एक काला धब्बा है तथा जिस पुलिस का दायित्व के जान-माल की रक्षा करना है वही सत्ता के संरक्षण में माफ़िया व डॉन की तरह करेंगे तो लोगों का सत्ता व पुलिस पर से विश्वास उठ जायेगा।

लोकसभा चुनाव प्रचार के समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस के विरुद्ध व्याप्त किसानों के असंतोष से चुनावी फ़ायदा उठाने के लिये किसानों से वादा किया कि सत्ता में आने के बाद स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे तथा फ़सलों का उचित दाम देंगे। परंतु सत्ता मिलने के साढ़े सार साल बाद भी मोदी सरकार द्वारा उनकी मांगे पूरी न करने पर हज़ारों की संख्या में किसानों ने अपनी मांगे मनवाने के लिये 2 अक्तूबर को हरिद्वार के टिकैत घाट से दिल्ली के किसान घाट की ओर कूच किया। परंतु मोदी सरकार की पुलिस ने उन्हें गाज़ीपुर बार्डर पर दिल्ली घुसने से रोक दिया। किसानों ने वहीं अपना डेरा जमा लिया तो पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिये उन पर लाठी चार्ज कर दिया। जिससे अनेक किसान जख्मी हुए।

मोदी से बड़ा झूठा न हुआ है न होगा, यह किसान की आवाज़!' में मोदी की झूठ कि 150 प्रतिशत एमएसपी दे दिया, कर्ज माफ़ कर दिया, स्वामीनाथन आयोग की सिफ़रिशें लागू कर दी आदि का कच्चा चिट्ठा खोला गया है।

किसानों की दुर्दशा का कारण उनका राज्यवार और क्षेत्रवार विभिन्न जातियों में बंटा होना है, जिसका 'विश्लेषण: किसान, राजनीति और दुर्गति' में सटीक विश्लेषण किया गया है। सब किसानों की समस्याएं साझा है लेकिन वो एक दूसरे की समस्या को साझा करने में झिझक जाते हैं। जिसका सत्ता हमेशा लाभ उठाती है। सीमांत किसान और खेत मज़दूर की दशा तो और भी खराब है बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिये छोटे-छोटे अप्रांसंगिक मुद्दों को ताक पर रखकर किसानों को अपनी समस्याओं के निपटारे के लिये लामबंद होकर आंदोलन करने की आवश्यकता है।

मोदी सरकार सरकारी कंपनियों व सरकारी उपक्रमों को अनावश्यक व बेकार बनाकर अपने पूंजीपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने पर तुली हुई है। इसके लिये मोदी सरकार अपनी आलोचनाओं व विरोध की भी परवाह नहीं करती। सरकारी उपक्रम एचएएल को नज़रअंदाज करके फ्रांसीसी कंपनी एविएशन से अनिल अम्बानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस से राफ़ेल डील करा दिया था। अब केंद्र सरकार के इशारे पर अंबानी की कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्य पाल मलिक ने राज्य के कर्मचारियों, पेंशनर और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिये सरकारी कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की बजाए रिलायंस जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की हेल्थ पॉलिसी लेना अनिवार्य कर दिया है, जिसको 'बिमा व्यवसाय में राज्यपाल बना अंबानी एजेंट' में उजागर किया गया है।

लखनऊ में बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐपल के मैनेजर विवेक तिवारी की पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या करने पर 'यूपी में दम है-मेरे घर भी 25 लाख और नौकरी की बहुत जरूरत है....मुझे गोली मार दो बाबू' कार्टून द्वारा योगी सरकार की पुलिस द्वारा एनकाउंट में किसी बेगुनाह की हत्या करने व सरकार द्वारा उसके परिवार को मुआवज़ा देने की नीति पर उचित कटाक्ष किया गया है।